

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-319/गृह-सी/2005.—चूंकि, राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व के, सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए, सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है;

और चूंकि, जिला दण्डाधिकारी, महासमुंद की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी, महासमुंद को यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 1 जुलाई, 2006 से 30 सितम्बर, 2006 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

Raipur, the 28th June 2006

NOTIFICATION

No. F-4-319/Home-C/2005.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active or are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of the State ;

AND WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Mahasamund, the State Government is satisfied that it is necessary so to do ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the provision to sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Mahasamund, may during the period from 1st July, 2006 to 30th September, 2006, if satisfied as provided in sub-section (2) of the said section, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची के अन्तर्गत सूचीकृत क्षेत्रों में, जहाँ यह आवश्यक है कि सुरक्षा के उपाय किए जाएं, ताकि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके, अतः राज्य सरकार द्वारा निर्देशित है कि जहाँ आवश्यक हो, उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठाए जाएं।